Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(भाग–3)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM108

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(भाग–3)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP

विषय सूची (Contents)

13.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक संबंध एवं क्षेत्रीय व्यापार	5–73
14.	बेरोज़गारी	74–96
15.	गरीबी	97–122
16.	खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक	123–149
17.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	150–162
18.	भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग	163–186
19.	पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र	187–214
20.	भारत में भूमि सुधार	215–238
21.	आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	239–308
22.	सतत विकास	309–320

अध्याय
13

भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक संबंध, क्षेत्रीय व्यापार एवं संगठन (India's Economic Relations with the International Community, Regional Trade and Orgnization)

13.1 विश्व व्यापार संगठन
13.2 डब्ल्यूटीओ और गैट
13.3 विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत
13.4 विश्व व्यापार संगठन की संरचना
13.5 डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत व्यापार समझौते
13.6 कृषि संबंधी समझौते
13.7 वर्तमान परिदृश्य
13.8 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
13.9 विश्व बैंक समूह
13.10 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन-अंकटाड
13.11 विश्व आर्थिक मंच
13.12 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
13.13 वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
13.14 खाद्य एवं कृषि संगठन
13.15 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
13.16 एशियाई विकास बैंक
13.17 एशियाई आधारिक-संरचना निवेश बैंक
13.18 अफ्रीकी विकास बैंक समूह
13.19 आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र
13.20 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
13.21 बिम्सटेक
13.22 हिंद महासागर तटीय संघ
13.23 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
13.24 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग
13.25 शंघाई सहयोग संगठन
13.26 परा-प्रशांत भागीदारी
13.27 समूह-7 और समूह-20
13.28 इब्सा
13.29 बेसिक
13.30 यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन
13.31 कैरीबियन समुदाय एवं साझा बाज़ार
13.32 मध्य अमेरिकी साझा बाज़ार
13.33 मध्य यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता
13.34 उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता
13.35 मध्य अफ्रीकी आर्थिक एवं मौद्रिक समुदाय
13.36 पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी साझा बाज़ार
13.37 पूर्वी अफ्रीकी समुदाय
13.38 आर्थिक सहयोग संगठन
13.39 लैटिन अमेरिकी एकता संघ
13.40 मर्कोसुर
13.41 दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय
13.42 पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक एवं मौद्रिक संघ
13.43 खाड़ी सहयोग परिषद
13.44 स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल
13.45 यूरोपीय संघ
13.46 बीटीआईए: व्यापक आधारित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते
13.47 यूरेशियन आर्थिक संघ
13.48 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स

एसेम (ASEM)	1996		53
एशियाई क्लीयरिंग यूनियन (ACU)	1974	तेहरान	9 (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव व म्याँमार)
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	24 Oct, 1945	न्यूयार्क	193 (दक्षिणी सूडान 193वाँ सदस्य)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. एशियाई आधारिक-संरचना निवेश बैंक [एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB)] के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2019

1. AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं।
2. AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है।
3. AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2018

1. ऑस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. चीन
4. भारत
5. जापान
6. यू.एस.ए.

उपर्युक्त में से कौन-कौन आसियान (ए.एस.इ.ए.एन.) के 'मुक्त व्यापार भागीदारों' में से हैं?

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 3, 4, 5 और 6
(c) केवल 1, 3, 4 और 5
(d) केवल 2, 3, 4 और 6

3. 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट) निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है?

UPSC (Pre) 2017

(a) उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी
(b) औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिये प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति
(c) व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप
(d) अधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक

4. समाचारों में आने वाला 'डिजिटल एकल बाज़ार कार्यनीति (डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी)' पद किसे निर्दिष्ट करता है? **UPSC (Pre) 2017**

(a) ASEAN को (b) BRICS को
(c) EU को (d) G20 को

5. 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट)' स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?

UPSC (Pre) 2017

1. यह कृषि वस्तुओं के लिये सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
2. यह कृषकों के लिये राष्ट्रव्यापी बाज़ार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. सार्वभौम अवसंरचना सुविधा (ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी) **UPSC (Pre) 2017**

(a) एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिये ASEAN का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिये गए साख (क्रेडिट) से वित्तपोषित है।

(b) गैर-सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिये विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारियों (PPPs) की तैयारी और संरचना-निर्माण को सुकर बनाता है।

(c) OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर-सरकारी विनिवेश संग्रहीत करने की क्षमता है।

(d) UNCTAD द्वारा वित्तपोषित उपक्रमण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है।

7. 'व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? **UPSC (Pre) 2017**

(a) यूरोपीय संघ

(b) खाड़ी सहयोग परिषद

(c) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

(d) शंघाई सहयोग संगठन

8. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2017**

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिये, केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2017**

1. भारत ने WTO को व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
3. TFA, जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी-कभी समा. चारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? **UPSC (Pre) 2016**

(a) WTO मामला

(b) SAARC मामला

(c) UNFCCC मामला

(d) FTA पर भारत-EU वार्ता

11. हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? **UPSC (Pre) 2016**

(a) रूबल (b) रैंड

(c) भारतीय रुपया (d) रेनमिनबी

12. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति [International Monetary and Financial Committee (IMFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2016**

1. IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है।
2. IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भाँति भाग लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2016

1. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ए.पी.ई.सी. (APEC) द्वारा की गई है।
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

14. समाचारों में कभी-कभी देखा जाने वाला 'यूरोपीय स्थिरता तंत्र (European Stability Mechanism)' क्या है? **UPSC (Pre) 2016**

(a) मध्य-पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिये EU द्वारा बनाई गई एक एजेंसी

(b) EU की एक एजेंसी, जो यूरोक्षेत्र (यूरोज़ोन) के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है

(c) सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

(d) सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

15. भारत निम्नलिखित में से किसका/किनका सदस्य है?

UPSC (Pre) 2015

1. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एशिया-पैसिफिक इकॉनमिक कोऑपरेशन)
2. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियान नेशंस)
3. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3

(d) भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं है।

16. मेकाँग-गंगा सहयोग में, जो छः देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश प्रतिभागी नहीं है/हैं?

UPSC (Pre) 2015

1. बांग्लादेश
2. कंबोडिया
3. चीन
4. म्याँमार
5. थाइलैंड

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये?

(a) केवल 1 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 5

17. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture)', 'एग्रीमेंट ऑन दि एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)' और 'पीस क्लॉज़ (Peace Clause)' शब्द प्रायः समाचारों में किन मामलों के संदर्भ में आते हैं? **UPSC (Pre) 2015**

(a) खाद्य और कृषि संगठन

(b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन

(c) विश्व व्यापार संगठन

(d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

18. BRICS के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2014

1. BRICS का पहला शिखर सम्मेलन रिओ दे जेनेरो में 2009 में हुआ था।
2. दक्षिण अफ्रीका BRICS समूह में अंत में शामिल हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

19. विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में विचार कीजिये:

1. इसका सृजन प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के स्थान पर हुआ।

2. इसकी स्थापना उरुग्वे दौर की वार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद की गई थी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

20. विश्व व्यापार संगठन के मार्गदर्शक एवं मूलभूत सिद्धांत के संदर्भ में विचार कीजिये:

1. व्यापार हेतु खुली सीमाओं को बढ़ावा देना।
2. सदस्यों द्वारा एवं सदस्यों के बीच गैर-भेदभावकारी व्यवहार की गारंटी।
3. गतिविधियों में पारदर्शिता की प्रतिबद्धता।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

21. WTO से संबंधित सिंगापुर मुद्दे के चार मुद्दों के तहत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

(a) निवेश (b) प्रतिस्पर्द्धा नीति

(c) सरकारी खरीद (d) प्रशुल्क नीति

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सिंगापुर, जेनेवा, सिएटल के बाद चौथे दौर की वार्ता, दोहा वार्ता थी।
2. दोहा की वार्ता को दोहा विकास दौर भी कहा गया।
3. दोहा मुद्दे के अंतर्गत निवेश सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण एवं विवादित मुद्दा रहा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दोहा विकास एजेंडा के अंतर्गत 'सेवा' एक प्रमुख विषय था।
2. वित्त का प्रवाह, आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत तीन चैनल में से एक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. युद्धकालीन समय का संरक्षणवाद तथा व्यापार विखंडन आर्थिक विकास को रोकने वाला या पीछे धकेलने वाला सिद्ध हुआ।
2. वैश्विक व्यापार एवं विनिमय दर की स्थिरता ने विदेशी पूंजी का व्यापक प्रवाह सुनिश्चित किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

25. निम्नलिखित में से क्षेत्रीय व्यापार समझौते के उत्तरदायी कारक कौन-से हैं?

1. नए बाज़ार एवं व्यापार अवसर।
2. भू-सामरिक एवं राजनीतिक हित।
3. अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकना।

कूट:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

26. एक ऐसा संघ, जिसमें सदस्य देश संघ में उत्पादित सामग्रियों पर निम्न व्यापार बाधाओं का प्रयोग करते हैं, कहलाता है–

(a) अधिमान्य व्यापार समझौता

(b) मुक्त व्यापार क्षेत्र

(c) सीमा-शुल्क संघ

(d) साझा बाज़ार

27. निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिये:

1. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा में शामिल वस्तुओं से प्रशुल्क में धीरे-धीरे कमी की जाती है या उन्हें समाप्त किया जाता है।

2. व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता के अंतर्गत निवेश एवं सेवाओं जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है।
3. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता (CEPA) से काफी व्यापक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. कैरीबियन समुदाय एवं साझा बाज़ार, 1973 में चागुआरामास संधि के तहत संगठित किया गया था।
2. उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता कनाडा और क्यूबा के बीच का व्यापारिक समझौता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. मर्कोसुर की स्थापना 1991 की असुनसियन संधि के फलस्वरूप हुई थी।
2. स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का गठन 1991 में रूस तथा 11 अन्य देशों, जो पहले सोवियत संघ के भाग थे, के द्वारा किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यूरोपीय संघ मुख्यतया यूरोप में अवस्थित 27 देशों का राजनीतिक-सामाजिक संघ है।
2. यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों पर लागू होने वाले मानक कानूनों के द्वारा एकल बाज़ार का विकास किया है, जो सभी देशों पर लागू होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (d)	4. (c)	5. (c)	6. (b)	7. (a)	8. (c)	9. (a)	10. (a)
11. (d)	12. (c)	13. (b)	14. (b)	15. (b)	16. (c)	17. (c)	18. (b)	19. (c)	20. (b)
21. (d)	22. (b)	23. (c)	24. (c)	25. (c)	26. (a)	27. (c)	28. (b)	29. (c)	30. (b)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. क्या उरुग्वे दौर संधि वार्ता ने और परिणामी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) करार ने विभिन्न देशों के आईपीआर शासनों में भिन्नताओं से प्रसूत व्यापार विवादों को सुलझाने में मदद की है? साथ ही ट्रिप्स के अनुरूप होने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइये। **UPSC (Mains) 2010**
2. आई.एम.एफ. की भूमिका की विश्व बैंक की भूमिका के साथ समानता और विषमता दर्शाइये। **UPSC (Mains) 2010**
3. "दोहा राउंड के पिछले कुछ सालों में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ताओं में, सेवाओं में दिखाई देने वाले लाभों का अनुसरण करने के लिये भारत कृषि मुद्दों पर अपने दृढ़ विचार में नरमी अपनाता प्रतीत होता है।" इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। **UPSC (Mains) 2009**
4. किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में एक 'संवृद्धि का इंजन' के रूप में कार्य करने में विफल हुआ महसूस किया जाता है? **UPSC (Mains) 2012**
5. यूरोप के तथाकथित पिग्स देशों में हाल के आर्थिक संकट के कारणों पर टिप्पणी कीजिये। **UPSC (Mains) 2010**
6. विश्व व्यापार, संघर्ष के मुकाबले सहयोग को ज़्यादा बढ़ावा देता है। टिप्पणी करें।

अध्याय
14

बेरोज़गारी
(Unemployment)

14.1 बेरोज़गारी
14.2 भारत में बेरोज़गारी के लक्षण
14.3 भारत में बेरोज़गारी
14.4 बेरोज़गारी से जुड़े महत्त्वपूर्ण आयाम
14.5 बेरोज़गारी के कारक
14.6 बेरोज़गारी के वर्गीकरण का आधार
14.7 बेरोज़गारी के प्रकार
14.8 भारत में बेरोज़गारी के कारण
14.9 शिक्षा और बेरोज़गारी
14.10 बेरोज़गारी के दीर्घकालिक परिणाम
14.11 बेरोज़गारी दूर करने के उपाय
14.12 रोज़गार सृजन के उपकरण
14.13 रोज़गार की प्रवृत्तियाँ
14.14 रोज़गार सृजन हेतु कुछ सामान्य अनुशंसाएँ
14.15 जनसांख्यिकीय लाभांश तथा रोज़गार योग्यता
14.16 रोज़गार विहीन संवृद्धि
14.17 वैश्वीकरण और रोज़गार
14.18 भारत में बेरोज़गारी दूर करने के मुख्य कार्यक्रम

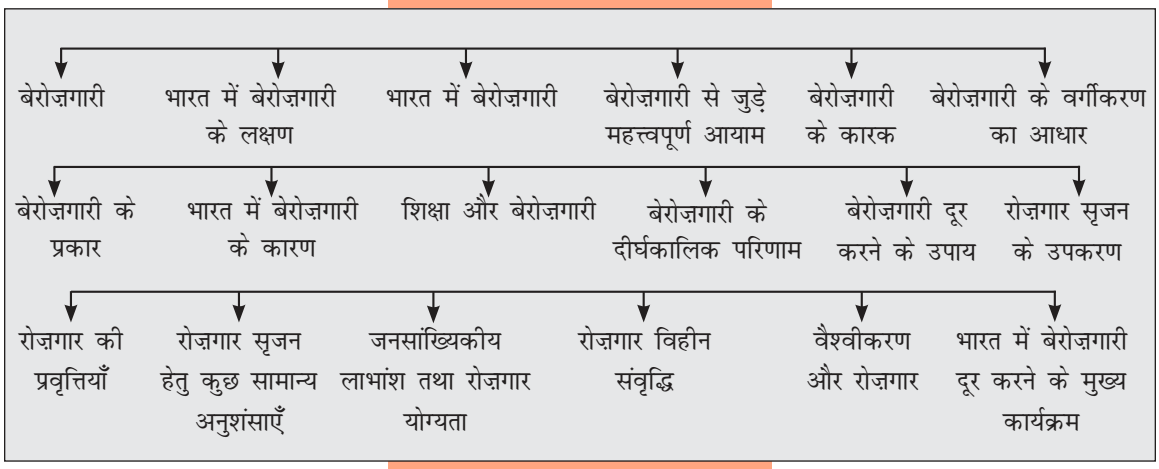

14.1 बेरोज़गारी *(Unemployment)*

बेरोज़गारी वह स्थिति है, जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोज़गार की खोज करता है, लेकिन वह काम पाने में अक्षम रहता है। बेरोज़गारी को सामान्यत: बेरोज़गारी दर के रूप में मापा जाता है। बेरोज़गारी दर, बेरोज़गार व्यक्तियों की वह संख्या है, जो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है।

एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है, जब वह प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिये तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता तब ऐसे व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' तथा ऐसी समस्या को 'बेरोज़गारी की समस्या' कहा जाता है।

14.2 भारत में बेरोज़गारी के लक्षण *(Features of Unemployment in India)*

- सामान्यत: हम लोग उस व्यक्ति को बेरोज़गार मानते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है या जिसे कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन यह पूर्णत: नहीं बल्कि अंशत: ही सही है। यह बात ज़्यादातर उन व्यक्तियों के मामले में सही है,जो शिक्षित हैं और काम पाने में सक्षम नहीं हैं या जो काम की तलाश में शहरों में आते हैं।

अध्याय
15

गरीबी
(Poverty)

15.1 गरीबी
15.2 सतत् विकास लक्ष्य-1: सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना
15.3 भारत में गरीबी को मापने से संबंधित विभिन्न समितियाँ
15.4 भारत में गरीबी
15.5 गरीबी को दूर करने के उपाय
15.6 कुछ महत्त्वपूर्ण सूचकांक
15.7 यूनिवर्सल बेसिक इनकम
15.8 गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ

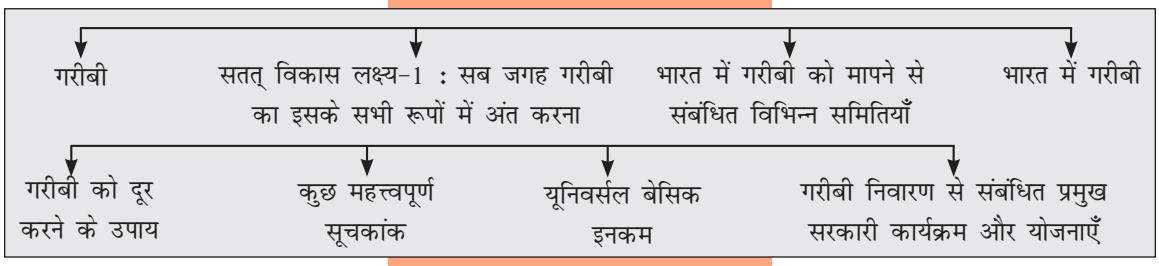

15.1 गरीबी *(Poverty)*

गरीबी वह स्थिति है, जब लोग भोजन, वस्त्र एवं आवास या आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। गरीबी मूलत: वंचन से संबंधित है।

गरीबी के प्रकार *(Types of Poverty)*

सामान्य रूप से गरीबी दो प्रकार की होती है-

1. **निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty):** निरपेक्ष गरीबी गंभीर अभाव (Severe deprivation) की स्थिति है, जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, जैसे– भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा तथा सूचना का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिये गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है। यह केवल आय पर ही नहीं बल्कि सेवाओं की पहुँच पर भी निर्भर करती है। इस तरह की गरीबी मुख्यत: अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में दिखाई देती है।
2. **सापेक्षिक गरीबी (Relative Poverty):** समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को 'सापेक्षिक गरीबी' कहते हैं अर्थात् सापेक्षिक गरीबी तब देखने को मिलती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। वे सामान्य जीवन जीने तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये संघर्ष करते हैं। सापेक्षिक गरीबी देश के अनुसार बहुसंख्यकों के जीवन स्तर के अनुसार बदलती रहती है। हालाँकि यह निरपेक्ष गरीबी की तरह तीव्र नहीं है, लेकिन यह काफी गंभीर एवं हानिकारक है। जिस समाज में पूर्ण समानता होती है, उस समाज में सापेक्षिक गरीबी नहीं होती है, किंतु विश्व में कहीं भी ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अत: विश्व के हर देश में सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी विकल्पों एवं अवसरों से वंचित करना एवं मानव गरिमा का उल्लंघन है। गरीबी के कारण व्यक्ति समाज में प्रभावी रूप से सहभागिता नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य परिवार के लिये भोजन एवं वस्त्र

अध्याय
16

खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक
(Food Security and Buffer Stock)

16.1 खाद्य सुरक्षा
16.2 खाद्य सुरक्षा का मुद्दा महत्त्वपूर्ण क्यों है?
16.3 वैश्विक भूख सूचकांकए 2018
16.4 सतत् विकास लक्ष्य-2: भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना
16.5 खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एवं सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रम
16.6 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
16.7 खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011
16.8 खाद्यान्न प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा
16.9 विश्व व्यापार संगठन और खाद्य सुरक्षा
16.10 खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
16.11 कृषि कीमत नीति
16.12 बफर स्टॉक

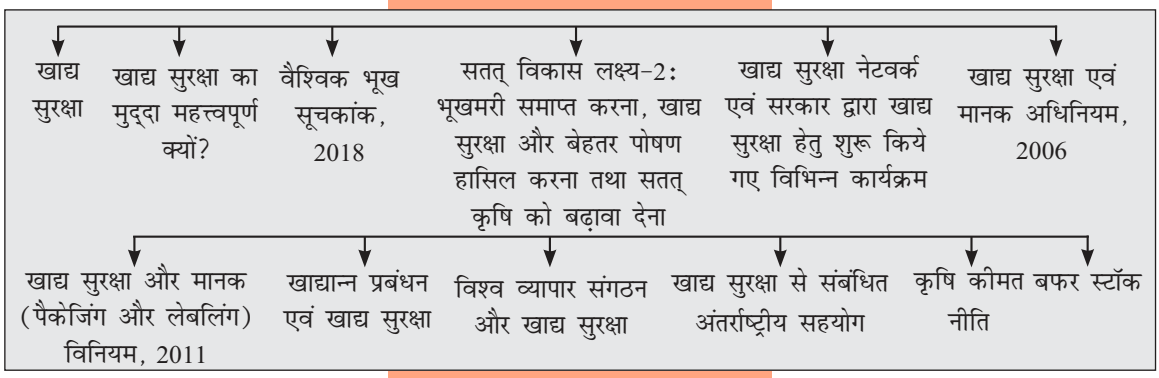

16.1 खाद्य सुरक्षा *(Food Security)*

खाद्य सुरक्षा वह अवस्थिति है, जब स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनयापन के लिये निरंतर पर्याप्त, सुरक्षित एवं पोषक खाद्य की उपलब्धता और इसकी सुगम पहुँच सुनिश्चित हो।

खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि समग्रता में खाद्यान्नों अर्थात् भोजन की उपलब्धता हो एवं इसके साथ-साथ व्यक्तियों व परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो, ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न खरीद सकें। जहाँ तक पर्याप्त उपलब्धता का संबंध है, इसके दो पहलू हैं:

- **मात्रात्मक पहलू:** अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धता इतनी हो कि मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति की जा सके।
- **गुणात्मक पहलू:** जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization–FAO) द्वारा खाद्य सुरक्षा की व्यापक व्याख्या की गई है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के लिये मूलत: निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है–

- **उपलब्धता:** खाद्यान्न हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- **किफायती:** खाद्यान्न किफायती होने चाहिये एवं लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये आर्थिक पहुँच होनी चाहिये अर्थात् नागरिकों के पास खाद्यान्नों की आवश्यक क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity–PPP) होनी चाहिये।
- **समावेशन:** खाद्यान्न सुरक्षित और पोषक होने चाहिये, ताकि वे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकें।
- **स्थिरता:** खाद्यान्न प्रणाली उचित रूप से स्थिर होनी चाहिये। खाद्यान्न प्रणाली में अधिक अस्थिरता का न केवल गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अपितु यह राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता को भी जोखिम में डाल देता है।

अध्याय
17

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System)

17.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली
17.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य
17.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास
17.4 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
17.5 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
17.6 अंत्योदय अन्न योजना
17.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान समस्याएँ/कमियाँ
17.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु उपाय
17.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिये की गई पहलें
17.10 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण
17.11 केंद्रीय सहायता
17.12 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पंचायती राज
17.13 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार की आवश्यकता
17.14 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
17.15 भारतीय खाद्य निगम
17.16 भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की रिपोर्ट

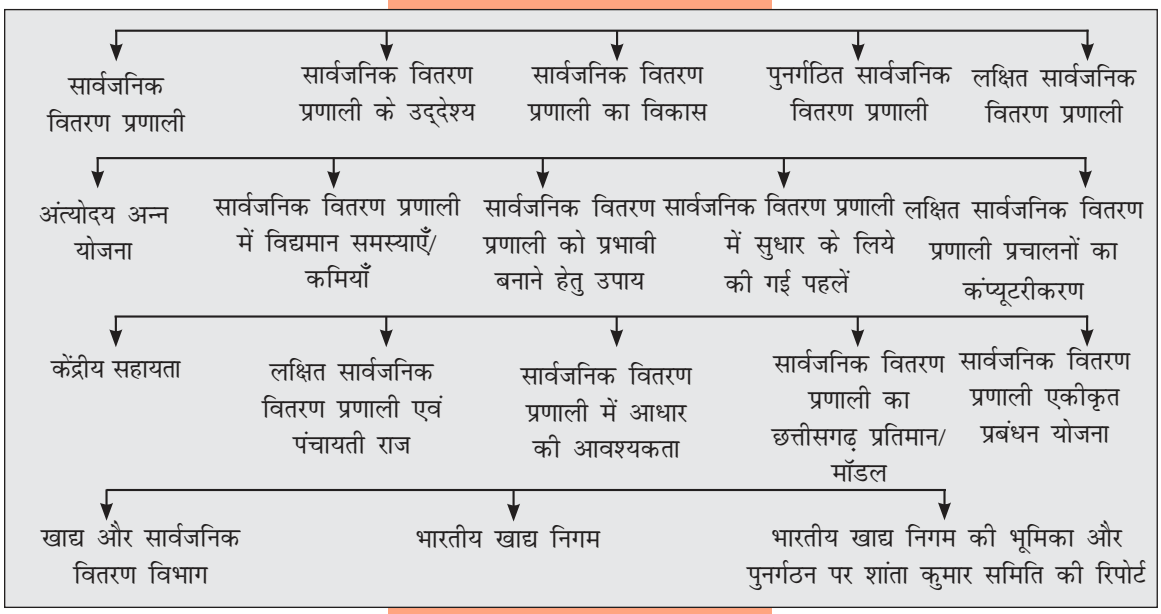

17.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(Public Distribution System)*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रमुख नीति है। इसका नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय एवं कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास अनाज के अभाव एवं वहनीय कीमतों पर उनके वितरण के प्रबंधन हेतु किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य प्रबंधन के लिये सरकार का प्रमुख नीतिगत उपकरण बन गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन तथा राज्य सरकारों को थोक आवंटन करती है। राज्य के अंदर

अध्याय
18

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
(Food Processing Industry in India)

18.1 खाद्य प्रसंस्करण
18.2 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सिंहावलोकन
18.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व
18.4 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये संभावनाएँ
18.5 खाद्य प्रसंस्करण के लाभ
18.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : मुख्य चुनौतियाँ
18.7 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये सुझाव
18.8 खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित वस्तुओं का निर्यात
18.9 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
18.10 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का SWOT विश्लेषण
18.11 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम
18.12 मेगा फूड पार्क तथा कृषि निर्यात ज़ोन
18.13 कोल्ड चेन, मूल्यवर्द्धन तथा संरक्षण संबंधी आधारभूत संरचना स्कीम
18.14 राष्ट्रीय कृषि बाज़ार
18.15 कृषि निर्यात नीति, 2018
18.16 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
18.17 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्तिशृंखला प्रबंधन
18.18 ऊपर एवं नीचे की अपेक्षाएँ
18.19 आपूर्तिशृंखला प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करना
18.20 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
18.21 निष्कर्ष

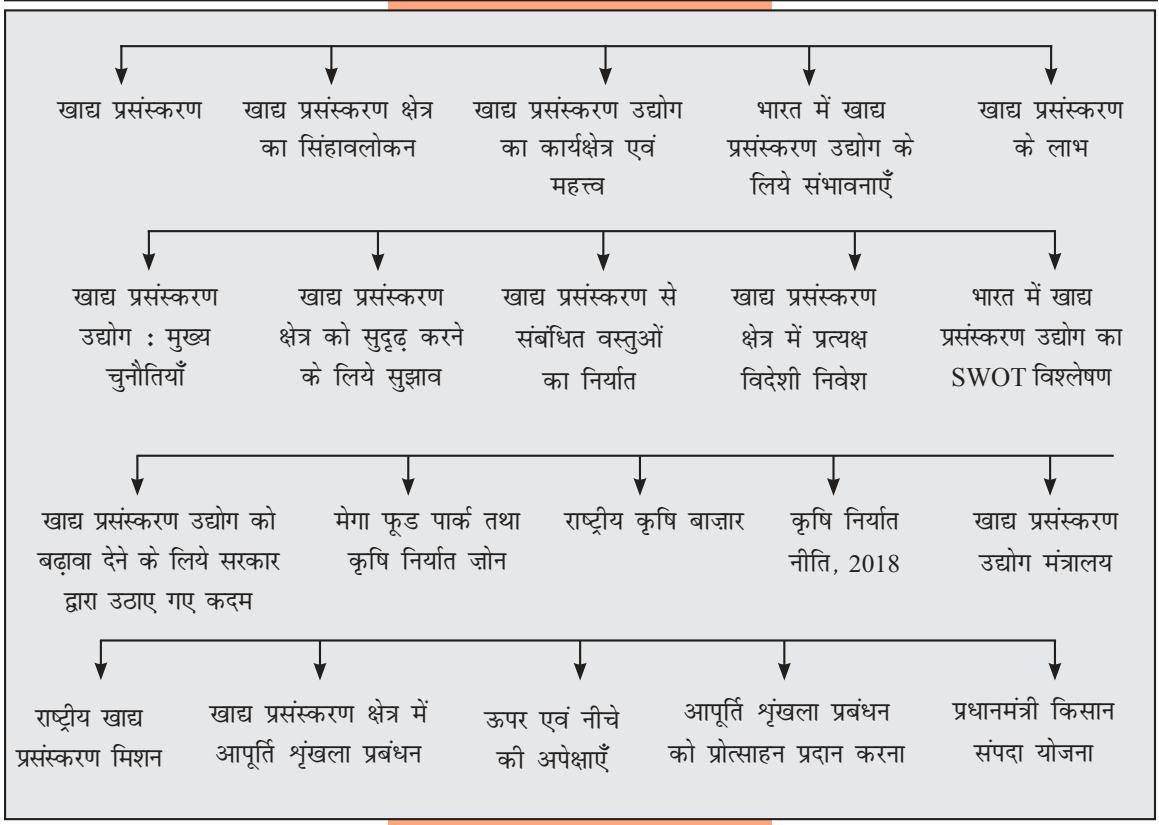

अध्याय
19

पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र
(Economics of Animal Husbandry)

19.1 परिचय
19.2 पशुपालन का महत्त्व
19.3 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका
19.4 पशुधन संगणना
19.5 पशुपालन के समक्ष समस्या
19.6 पशुपालन की समस्या से निपटने हेतु सरकारी उपाय
19.7 डेयरी
19.8 मत्स्यपालन
19.9 मधुमक्खी पालन
19.10 मुर्गीपालन/कुक्कुट पालन
19.11 रेशम कीट पालन
19.12 पशुधन धारिता पर NSSO की रिपोर्ट
19.13 पशुओं की खरीद-फरोख्त के लिये नियम
19.14 पशुपालन और रोज़गार
19.15 पशुपालन की निर्यात क्षेत्र में भूमिका
19.16 पशुपालन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
19.17 पशुपालन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट
19.18 पशुपालन संबंधी वर्तमान परिदृश्य

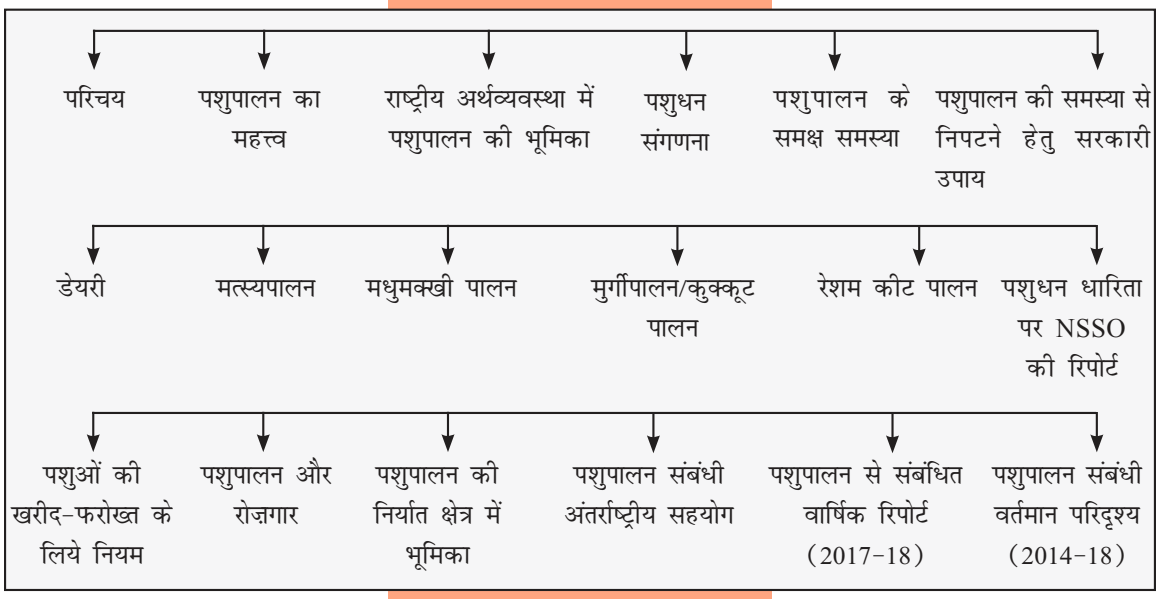

19.1 परिचय *(Introduction)*

विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में पशुपालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह आजीविका से जुड़े कई उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देता है और गरीबी से बाहर निकलने में भी मददगार होता है। पशुपालन गरीबों के लिये बीमा संपत्ति के समान है। गरीबों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार कर यह मानव पूंजी को समृद्ध बनाता है। वर्षों से पशु स्रोत आधारित खाद्य मानव विकास के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पशुओं को पालतू बनाने तथा स्थायी कृषि के माध्यम से खाद्य आपूर्ति को स्थिरता प्राप्त हुई एवं इससे सामाजिक विकास के लिये ऊर्जा प्राप्त हुई। आज पशुपालन सामाजिक परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि पशु गरीब जनसंख्या के लिये महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति हैं। निम्न आय वाले देशों में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य आय को बढ़ाना तथा पशु आधारित खाद्य (Animal Sourced Food) की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इन प्रयासों को तकनीकों के माध्यम से और भी बल मिलता है, क्योंकि इससे किसी विशेष पशु की उत्पादकता को अधिकतम किया जा सकता है। हालाँकि यह विकासशील देशों के मामले में पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है।

अध्याय
20

भारत में भूमि सुधार
(Land Reforms in India)

20.1 भूमि सुधार
20.2 भूमि सुधार के उद्देश्य
20.3 भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता एवं महत्त्व
20.4 स्वतंत्रता-पूर्व भारत में भू-राजस्व प्रणालियाँ
20.5 स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा
20.6 भूमि सुधारों में कमियाँ
20.7 भूमि सुधार कार्यक्रमों की सफलता के लिये सुझाव
20.8 भूमि सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा
20.9 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
20.10 विभिन्न योजनाओं के दौरान भू-सुधार
20.11 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और (संशोधन) अध्यादेश, 2015
20.12 कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम, 2016

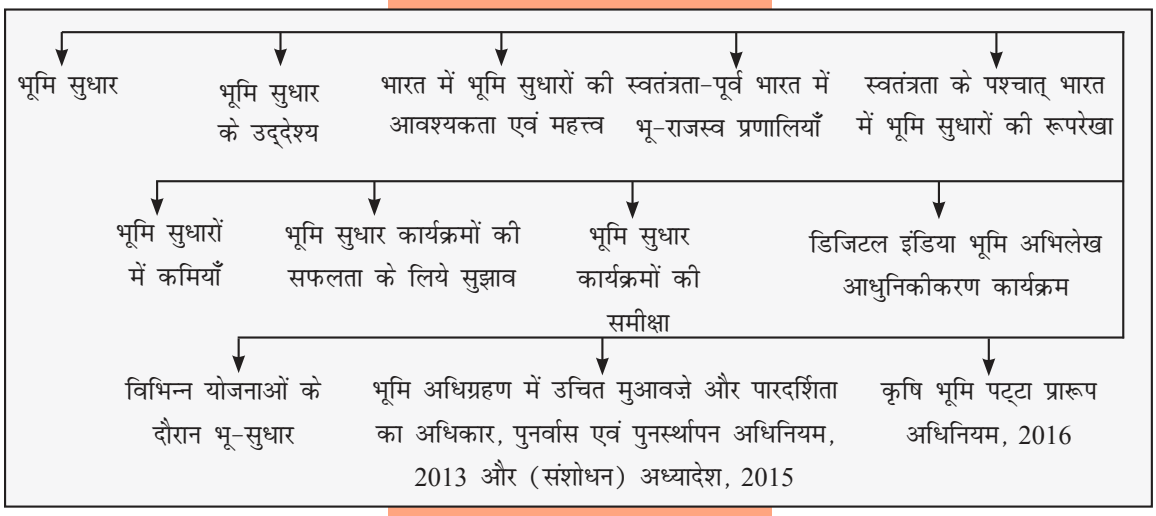

20.1 भूमि सुधार *(Land Reforms)*

'भूमि सुधार' से अभिप्राय है- भू-स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना अर्थात् भू-धारिता (Land-Holdings) को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि एक मूलभूत प्राकृतिक एवं सीमित संसाधन है। अंग्रेज़ी शासन से पूर्व अर्थात् मुगल काल में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। कृषक को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक ही था, जब तक वह स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ भाग (अनाज का हिस्सा) देता रहा। औपनिवेशिक शासन में विभिन्न ब्रिटिश नीतियाँ उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिये बनाई गई थीं एवं ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना था, इसलिये उन्होंने कई भू-राजस्व प्रणालियाँ शुरू कीं, जैसे- ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इस प्रकार प्रचलित नीतियों एवं व्यवस्थाओं के कारण भू-स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिये एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिये भूमि-सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

भूमि सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के अंतर्गत रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को

अध्याय
21

आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (Effects of Economic Reforms and Liberalization on the Indian Economy)

21.1 परिचय
21.2 भारत की विकास रणनीति
21.3 1991 से पूर्व की आर्थिक नीतियों के मुख्य बिंदु
21.4 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों की शुरुआत
21.5 1991 से आर्थिक सुधार
21.6 1991 के बाद आयोजन में आए संरचनात्मक बदलाव
21.7 आयोजन में आए संरचनात्मक बदलाव के कारण
21.8 1991 की नई आर्थिक नीति के आयाम
21.9 उदारीकरण
21.10 आर्थिक सुधार एवं संवृद्धि
21.11 सुधारों से जुड़ी आर्थिक स्थिरता
21.12 भारत में औद्योगिक क्षेत्र
21.13 औद्योगिक क्षेत्र
21.14 औद्योगिक क्षेत्र का महत्त्व
21.15 औद्योगिक नीतियाँ
21.16 औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
21.17 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
21.18 कोर इंडस्ट्रीज
21.19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
21.20 महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के उद्योग
21.21 औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण
21.22 विज़न न्यू इंडिया 2022-सीपीएसई की भूमिका और कार्य को पुन: परिभाषित करना
21.23 स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया /75 में औद्योगिक क्षेत्र के लिये प्रावधान
21.24 चौथी औद्योगिक क्रांति
21.25 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
21.26 भारत में असमाविष्ट गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के मुख्य संकेतक रिपोट
21.27 एमएसएमई के पुनरुद्धार हेतु आरबीआई पैनल
21.28 विशेष आर्थिक क्षेत्र
21.29 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
21.30 विनिवेश
21.31 औद्योगिक अस्वस्थता/रुग्णता
21.32 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016
21.33 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011
21.34 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण ज़ोन
21.35 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
21.36 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
21.37 राज्य वित्त निगम
21.38 शेल कंपनी
21.39 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
21.40 कंपनी अधिनियम, 2013
21.41 कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2019
21.42 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
21.43 भारत में औद्योगिक विकास के सम्मुख समस्याएँ/बाधाएँ
21.44 जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव
21.45 कारोबार सुगमता सूचकांक, 2019
21.46 औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम
21.47 नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, 2016
21.48 आठवीं-बारहवीं पंचवर्षीय योजनाएँ
21.49 आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992.97
21.50 नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997.2002
21.51 दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002.2007
21.52 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007.2012
21.53 बारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2012.2017
21.54 भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ-लक्ष्य, उपलब्धियाँ एवं उद्देश्य
21.55 इंडिया विज़न 2020

अध्याय
22

सतत् विकास
(Sustainable Development)

21.1	प्रस्तावना	21.5	सतत् विकास हेतु भारत के प्रयास
21.2	सतत् विकास से संबंधित कारक	21.6	क्या हैं सतत् विकास लक्ष्य-6?
21.3	सतत् विकास के लिये स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मज़बूत बनाना	21.7	सतत् विकास लक्ष्य और भारत
		21.8	मानव विकास रिपोर्ट-2018
21.4	मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय	21.9	संधारणीय विकास लक्ष्य, 2018

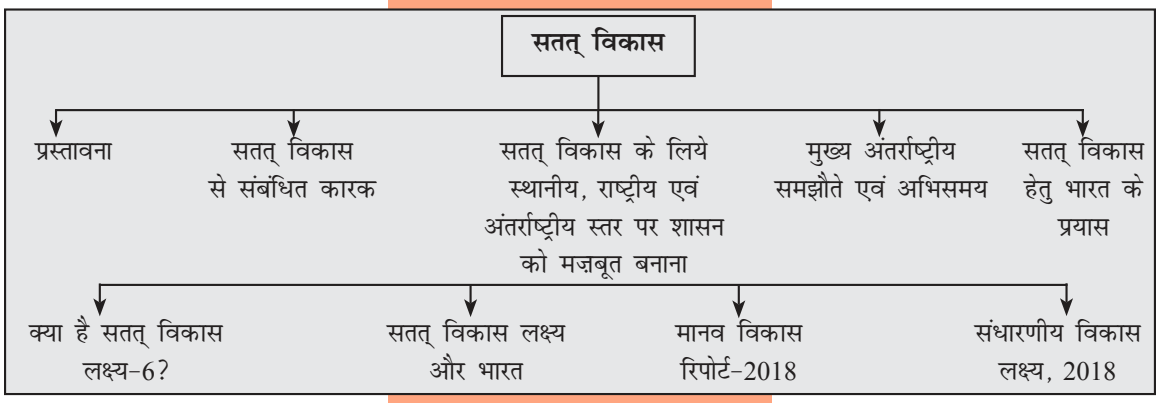

22.1 प्रस्तावना *(Introduction)*

सतत् विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। इसका विकास इस तरह से होता है कि व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित परिणामों पर विचार कर लेना चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे निर्णय एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा हमारे कार्यों का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में सतत् विकास ऐसा विकास है, जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

'सतत् विकास' शब्द का प्रयोग 1980 के दशक के अंत में 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) नामक रिपोर्ट जिसे 'द ब्रंटलैंड रिपोर्ट' (The Brundtland Report) के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद व्यापक रूप से किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिये परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन-सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिये पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। इस आयोग का औपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (The World Commission on Environment and Development) था। इसने मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उस क्षय के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। आयोग की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशिष्ट रूप से दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था-

- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर्संबंधित हैं।
- सतत् विकास के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596